Business	Time allotted
6. Discussion on the Statutory Resolution seeking approval of the Proclamation issued by the President under Article 356 of the Constitution in respect of (the State of Bihar	3 hours

The Committee also recommended that the Private Members' Legislative Business scheduled for Friday, the 18th March, 2005 may be taken up on Thursday, the 24th March, 2005.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Dipankar Mukherjee, you want to say something.

MATTERS RAISED WITH THE PERMISSION

Demand for a white paper on efforts to revive Enron-Dhabhol Power Project

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, I want to bring to the notice of the House...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please be brief.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, I will take only two minutes. I will mention only two major points regarding the infamous Enron-Dhabhol Power Project which is sought to be revived again. As you are aware, the whole House is aware, the Indian banks and financial institutions have already sunk in Rs. 3,600 crores. Now, we have information that these Indian lenders, whose money has become NPAs, is being written off, are being asked to liquidate the dues of the foreign banks to the tune of Rs. 2,000 crores. So far as the Indian banks are concerned, Rs. 3,600 crores are already NPAs for this unviable project. But they have been asked to make a special project vehicle which is being known as Gas and Power Investment Company Limited. And they are trying to raise this money from the Employees' Provident Fund, EPFO and LIC, on bonds to be guaranteed by the Government of India. My first question is: The Government must clarify...*(Interruptions)...*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Today, there is nobody to answer the question.. .*(Interruptions)...*

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: What appears to me is that in this globalised atmosphere, Indian Banks' NPAs are NPAs and foreign banks' NPAs are not NPAs. That money has also to be paid from the employees'

Provident Fund or from the LIC policy-holders' fund. My second point is that the NTPC and the GAIL, without any formal Executive order, without any formal notification, are being unofficially involved in the consultancy process for the revival of this Dhabhol Project; and they are being pressurised even to invest Rs. 500 crores. My submission, through you, to the Government is, so far as this Dhabhol Power Corporation is concerned, a White Paper must be submitted, before the House, right from the 13-day rule, when the 13-day rule was there in this country in 1996...*{Interruptions)...* and a counter-guarantee was approved from that day onwards, the whole bouquet, a White Paper must be laid before the House. Without that White Paper and without due diligence of the future viability of the Dhabhol Power Corporation, no public sector should be involved in this job.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA(West Bengal): Sir, this is a very serious matter. *{Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. The Chairman has allowed only two Members to speak on this issue. Shri C. Ramachandraiah.

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): Sir, what we read in the newspapers, if that is correct, it is a very alarming issue. Sir, to redeem a foreign loan account of a security in this country, by utilising the funds of the employees hard-saved earnings, is highly detrimental to the interest of the working force. I have information that you are going to revive this unit If you have to do it, do it. But it is very unlawful and unethical on your part to use the funds of the employees. You used the funds of the employees. You are going to indulge in disinvestment, you are going to transfer that amount to the National Disinvestment Board. If at all, you want to revive this unit, kindly utilise the sale proceeds of those units for this purpose. Don't create such a vacuum in this country by utilising the funds of the employees. This project was a notorious project, and there are so many skeletons in so many cupboards. I do not want to go into the details. But let us not utilise the precious savings of the working class of this country.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Let the Government come out with a White Paper on this issue. This is my submission.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : आदरणीय उपसभापति महोदय, यह जानकारी में है कि दाभोल पावर प्रोजेक्ट के संबंध में, जो पी0पी0ए0 का एग्रीमेंट हुआ था, वह 8 दिसम्बर, 1983

को महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड और दाभोल पावर कम्पनी के बीच में हुआ था। जो इसका फर्स्ट फेज 7040 मेगावाट पावर सप्लाई करने का था, वह कम्पलीट हो चुका था। यह सन् 2001 के बाद आइडियल पॉजिशन में है। इस विषय में, पिछले कई दिनों से जो डिस्प्युट्स हुए हैं, उनके समाधान के लिए कई प्रयास किए गए ताकि इस प्रोजेक्ट को रिवाईव किया जा सके । सरकार ने विभिन्न पहलूओं को दृष्टिगत रखते हुए, दाभोल पावर प्रोजेक्ट के विषय में एमपावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक कमेटी गठित की है। उसकी अनेक पीटिंग्स हो चुकी है और उसमें यह बात गंभीरता से ली जा रही है कि कैसे यह प्रोजेक्ट वायबल हो सके, कैसे सह चल सके । माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, उसमें यह बात भी शामिल है कि इंडियन फाइनेंशियल इंस्टिटटूशन्स का पैसा, कैसे वापस मिल सके, इन बिन्दुओं का समावेश भी उसमें किया गया है । मैं यह बताना चाहता हूं कि इसमें सरकार मात्र फैसिलेटेटर का काम कर रही हैं। इस विषय में ई.जे.एम. की अनेक मीटिंग हो चुकी है, अनेक विकल्पों पर विचार चल रहा है । चूंकि अभी यह विषय नेगोसिएशन्स की स्टेज पर है, इसलिए इस अवसर पर यह उचित नहीं होगा कि सारी बातों का जिक्र जाए, लेकिन जो बातें माननीय सदस्य ने उठाई हैं, ई.जे.एम. की और मीटिंग्स होगी तथा इसमें सारे विकल्प खुले रखे हैं, उन पर ध्यान रखा जाएगा ।

Payment of Arrears to Sugarcane Growers of Uttar Pradesh

श्री उपसभापति : श्री हरेन्द्र सिंह मलिक । आप संक्षिप्त में बोलिए ।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक (हरियाणा) **:** महोदय, मैंने यहां बार-बार गन्ना किसानों के बारे में अनुरोध किया है । वर्ष 2000-2003 में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 600 करोड़ रूपए से ज्यादा निजी चीनी मिलों की तरफ बकाया है । निजी चीनी मिल के मालिक उत्तर प्रदेश विकास परिषद् के सदस्य भी है । मान्यवर, यही नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी गन्ना किसानों को उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है और इस पर संवैधानिक पीठ का आदेश भी आ चुका है। जब इसके बाद सरकार को अवमानना का नोटिस गया, 35 निजी चीनी मिल मालिकों को गया, प्रिंसिपल सैक्रेटरी शुगरकेन को गया, कमिश्नर शुगरकेन को गया तो 35 चीनी मिल मालिकों ने तो जो कहा, वह कहा ही, उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों अधिकारियों की ओर से एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होकर यह कहा है कि सब पैसा दे दिया गया है और जो रह गया है, वह भी दे दिया जाएगा। किसान प्रतिनिधि वी.एम. सिंह ने, इसके बाद अपमानना का नोटिस दे दिया कि असत्य बोल रहे हैं, सत्य से परे बोल रहे है। शपथ-पत्र दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट को पूरे विभाग की सूचना दे दी गई । मान्यवर, निजी चीनी मिल मालिकान कुडंली मारकर बैठे हैं, वे 600 करोड़, 700 करोड़ रूपए दे नहीं पा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत केन्द्र सरकार का दायित्व बनता है कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराए । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि किसान जो गन्ना आपूर्ति करते हैं ...(**व्यवधान**)...